शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रिटायर्ड हर्ट पर चुप्पी तोड़ी

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'द ओडिसी' की कहानी भारतीय दर्शकों को क्यों लगती है इतनी अपनी?

Page-05

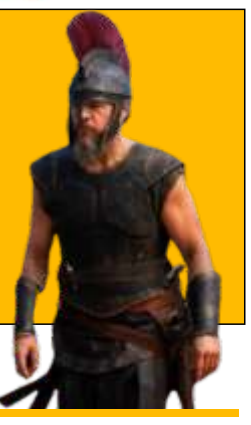

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी शुभकामनाएं

ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में शुरू हो गई है। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इस उत्सव को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आस्था और सामाजिक समरसता की शानदार अभिव्यक्ति है। उन्होंने कामना की कि महाप्रभु जगन्नाथ सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए इसे लोगों को जोड़ने वाला और मानवता का संदेश देने वाला पर्व बताया।पुरी के श्रीमंदिर के सिंहद्वार पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के तीनों विशाल रथ पूरी भव्यता के साथ सजाए गए हैं। लाखों श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन और रथ खींचने के लिए पुरी पहुंचे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस वर्ष भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए हैं।रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहन के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा लगभग नौ दिनों तक चलती है और इसके बाद भगवान की वापसी 'बहुदा यात्रा' के रूप में होती है। इस अवसर पर पूरे पुरी शहर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। रथ यात्रा को लेकर धार्मिक उत्साह के साथ प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चिकित्सा शिविर, कंट्रोल रूम और आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय रखा गया है। हर साल की तरह इस बार भी रथ यात्रा भारत की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक आस्था का भव्य उत्सव बनकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है।

BIMSTEC बैठक में अजित डोभाल का बड़ा संदेश

सुरक्षा और विकास साथ-साथ चलें तभी मजबूत होगा क्षेत्र

नई दिल्ली में आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने ऐसा संदेश दिया, जिसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बैठक में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद रहे। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, आतंकवाद और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा को सबसे प्रभावी समाधान बताया।अपने संबोधन में अजित डोभाल ने कहा कि आज सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। साइबर अपराध, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, संगठित अपराध, मानव तस्करी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। इनसे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अकेले इन खतरों का सामना नहीं कर सकता।डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन या संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ और आतंकी वित्तपोषण पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई। इसके साथ ही उन्होंने समुद्री सुरक्षा को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने सभी सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के जरिए भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति और सामूहिक सुरक्षा को भी समान महत्व देता है। बदलते वैश्विक हालात में भारत की यह पहल दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप फाइनल में

फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के सबसे बड़े नायक कप्तान लियोनेल मेसी रहे, जिन्होंने मैच के निर्णायक क्षणों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई। अब फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है।मैच की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कड़े मुकाबले के साथ हुई। पहले हाफ में इंग्लैंड ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया और अर्जेंटीना के हमलों को काफी हद तक रोकने में सफलता हासिल की। हालांकि दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने आक्रामक रणनीति अपनाई और लगातार दबाव बनाना शुरू किया।मैच के अंतिम मिनटों में लियोनेल मेसी ने अपने अनुभव और शानदार फुटबॉल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले बेहतरीन मूव तैयार कर टीम को बराबरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई और फिर निर्णायक हमला करते हुए अर्जेंटीना के लिए विजयी गोल का रास्ता बनाया। मेसी के प्रदर्शन की दुनिया भर में सराहना हो रही है और फुटबॉल विशेषज्ञ इसे उनके करियर के सबसे यादगार विश्व कप प्रदर्शनों में से एक बता रहे हैं।

मौलाना जरजिस अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के बाद मौलाना जरजिस अंसारी विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मौलाना यह दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि "भगवान कृष्ण दिन में पांच बार नमाज अदा करते थे।" यह बयान सामने आने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है।बताया जा रहा है कि यह भाषण झारखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। हालांकि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की और कई स्थानों पर मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। कई संगठनों ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक महापुरुषों के बारे में इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। विवाद ऐसे समय सामने आया है जब श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। कई धार्मिक नेताओं ने कहा कि किसी भी धर्म या उसके आराध्य के बारे में बिना प्रमाण इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू, 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला

देश इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पर्यटकों और आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान केवल अधिकृत अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और समारोह की तैयारियों से जुड़े कर्मचारियों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह में राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, विदेशी राजनयिक, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विशेष अतिथि शामिल होंगे। इसी कारण सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी। लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, फेस रिकग्निशन तकनीक और एंटी-सबोटाज जांच जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जा सकता है।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे इस अवधि में लाल किले की यात्रा की योजना न बनाएं। इसके बजाय वे 16 अगस्त के बाद यहां घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं, जब स्मारक दोबारा आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है और इसकी तैयारियां कई सप्ताह पहले शुरू हो जाती हैं। लाल किले में होने वाला समारोह देश की लोकतांत्रिक परंपरा, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक माना जाता है। इस बार 80वीं वर्षगांठ होने के कारण समारोह को पहले से अधिक भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है।

संपत्ति बेचने वालों को मिलेगा टैक्स में बड़ा फायदा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नए वित्त वर्ष के लिए CII को बढ़ाकर 384 कर दिया गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में यह 376 था। इस फैसले से विशेष रूप से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो जमीन, मकान, सोना, चांदी या अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री करते हैं।कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का उपयोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की गणना में किया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को समायोजित करना होता है ताकि संपत्ति की वास्तविक लागत को वर्तमान मूल्य के अनुरूप माना जा सके। जब CII बढ़ता है तो खरीद लागत भी अधिक मानी जाती है, जिससे कर योग्य पूंजीगत लाभ कम हो जाता है और अंततः टैक्स का बोझ घटता है।विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कई वर्ष पहले संपत्ति या कीमती धातुएं खरीदी थीं और अब उन्हें बेचने की योजना बना रहे हैं। नई दर लागू होने से उनकी इंडेक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी और टैक्स देनदारी पहले की तुलना में कम हो सकती है।चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि यह बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। हालांकि उन्होंने करदाताओं को सलाह दी है कि संपत्ति बेचने से पहले टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें ताकि नए नियमों के अनुसार सही गणना की जा सके। सरकार का मानना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर CII में संशोधन करना जरूरी है, ताकि कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत और व्यावहारिक बनी रहे। नए इंडेक्स के लागू होने से लाखों करदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो दीर्घकालिक निवेश के जरिए संपत्ति से मुनाफा कमाते हैं।

जेलेंस्की के फैसले पर उठे सवाल

रक्षा मंत्री को हटाने पर सड़कों पर उतरी जनता

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। उनके अनुसार रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिर्स्की के बीच तालमेल पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिससे युद्ध संचालन प्रभावित होने की आशंका थी।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन इस समय गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को पद से हटाने के फैसले ने पूरे देश में विरोध की लहर पैदा कर दी है। राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। युद्ध शुरू होने के बाद यह सरकार के खिलाफ सबसे बड़े जन प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फेदोरोव ने रक्षा मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उन्हें यूक्रेन की सैन्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने, ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने और हथियारों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे समय में, जब रूस के साथ युद्ध निर्णायक दौर में है, उनका हटाया जाना सेना और देश दोनों के हित में नहीं माना जा रहा। कई प्रदर्शनकारियों ने "फेदोरोव को वापस लाओ" और "देश को सुधार चाहिए" जैसे पोस्टर लेकर राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष नेतृत्व के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। उनके अनुसार रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख जनरल ओलेक्सांद्र सिर्स्की के बीच तालमेल पूरी तरह खत्म हो चुका था, जिससे युद्ध संचालन प्रभावित होने की आशंका थी। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के समय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सरकार को यह कठिन फैसला लेना पड़ा।हालांकि विपक्षी दलों, कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नागरिक संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि फेदोरोव के नेतृत्व में यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध तकनीक, विशेष रूप से ड्रोन और डिजिटल रक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की थी। कुछ सैन्य अधिकारियों ने तो उनके समर्थन में अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया। विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का असर सेना के मनोबल और सरकार की लोकप्रियता दोनों पर पड़ सकता है। इसी बीच यूक्रेनी संसद ने व्यापक कैबिनेट फेरबदल के तहत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जबकि रक्षा मंत्रालय के नए नेतृत्व को लेकर अभी भी चर्चा जारी है। यूरोपीय देशों और पश्चिमी सहयोगी इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध के बीच यूक्रेन की राजनीतिक स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि सरकार जनता की नाराजगी कम करने में सफल नहीं हुई, तो इसका असर न केवल घरेलू राजनीति बल्कि रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध पर भी पड़ सकता है।

म्यांमार के तट पर बड़ा समुद्री हादसा, दो नावें डूबने से 500 से अधिक लोगों की मौत की आशंका

म्यांमार के तटीय क्षेत्र में 16 जुलाई को एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया, जिसने पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया को झकझोर कर रख दिया। खराब मौसम और ऊंची लहरों के बीच यात्रियों से भरी दो नावें समुद्र में डूब गईं। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों के अनुसार हादसे में 500 से अधिक लोगों के मारे जाने या लापता होने की आशंका जताई जा रही है। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जा रही है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों नावों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और विस्थापित परिवार सवार थे। समुद्र में अचानक मौसम खराब होने के बाद तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठीं, जिससे नावों का संतुलन बिगड़ गया और वे कुछ ही मिनटों में पानी में समा गईं। कई यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज धाराओं के कारण अधिकांश लोग लापता हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही म्यांमार की नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन ने बड़े स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। राहत कार्य में हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज और गोताखोरों की विशेष टीमों को लगाया गया है। हालांकि खराब मौसम और समुद्र की ऊंची लहरों के कारण बचाव अभियान में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि कई शव भी बरामद किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राहत एजेंसियों ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए आपातकालीन अभियान शुरू कर दिया है। पड़ोसी देशों ने भी म्यांमार को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहयोग देने की पेशकश की है।

राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल में होना है, जिसके लिए वहां तैयारियां चल रही हैं। इस प्रोग्राम में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है और राहुल गांधी के दौरे से पहले वहां तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तराखंड सरकार से 2025 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य का नकल-रोधी कानून बेअसर रहा और "सिर्फ कागजों पर" ही सीमित रहा, जबकि परीक्षा के पेपर बिकते रहे। 'छात्रों की गूंज' नाम के देशव्यापी अभियान के तहत, विपक्ष के नेता (LoP) 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे और राज्य की राजधानी में युवाओं से बातचीत करेंगे। इस देशव्यापी अभियान का मकसद छात्रों की समस्याओं, जैसे परीक्षा में गड़बड़ी और भारत की शिक्षा व्यवस्था की हालत पर ध्यान दिलाना है।एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने आरोप लगाया कि 'देवभूमि' के नाम से मशहूर उत्तराखंड "पेपर लीक का केंद्र" बन गया है और उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "मैं 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं। लेकिन उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि 'देवभूमि' को पेपर लीक का केंद्र बना दिया गया है। 2025 में हुई UKSSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए, गांधी ने दावा किया कि एक ऐसा "सिस्टम" बन गया है जिसमें सरकारी पद मेरिट के बजाय दूसरे तरीकों से हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "UKSSSC परीक्षाओं को लेकर यहाँ एक ऐसा 'सिस्टम' बन गया है, जहाँ पटवारी या लेखपाल जैसे पद मेरिट से नहीं, बल्कि अपराधियों द्वारा तय की गई कीमतों पर हासिल किए जाते हैं। अक्टूबर 2025 में, पेपर लीक के बड़े विवाद के बाद, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने ग्रेजुएट-लेवल भर्ती परीक्षा (जिसमें पटवारी, लेखपाल और सात अन्य पदों के लिए 416 रिक्तियां शामिल थीं) रद्द कर दी। 21 सितंबर, 2025 को राज्य के सभी जिलों में हुई लिखित परीक्षा को गहन जांच के बाद पूरी तरह से "रद्द" घोषित कर दिया गया।

दक्षिण चीन सागर में फिर बढ़ा टकराव चीन और फिलीपींस के जहाज आमने-सामने

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।16 जुलाई को विवादित समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के तटरक्षक जहाज आमने-सामने आ गए, जिसके बाद पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता और गहरा गई। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के तटरक्षक बल ने उसके सरकारी जहाजों को विवादित इलाके में मिशन पूरा करने से रोकने की कोशिश की और खतरनाक तरीके से उनके बेहद करीब पहुंचकर दबाव बनाया।फिलीपींस के तटरक्षक बल के अनुसार उसके जहाज नियमित आपूर्ति मिशन पर थे, लेकिन चीनी जहाजों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। फिलीपींस ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) का उल्लंघन बताया। मनीला ने कहा कि वह अपने वैध समुद्री अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और विवादित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी जारी रखेगा।वहीं चीन ने फिलीपींस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित समुद्री क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। बीजिंग का दावा है कि फिलीपींस के जहाज बिना अनुमति उसके जलक्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकना आवश्यक था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी तटरक्षक एजेंसियों ने कानून के अनुसार कार्रवाई की और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण चीन सागर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा यहां तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने का अनुमान भी लगाया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई सहित कई देशों के दावे हैं।घटनाक्रम के बाद अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी दोहराई और कहा कि वह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन के लिए प्रतिबद्ध है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की अपील की है।

ईरान-अमेरिका तनाव फिर बढ़ा, खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट सैन्य गतिविधियों ने बढ़ाई वैश्विक चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव तेजी से बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी ने 16 जुलाई को नया मोड़ ले लिया, जब फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। अमेरिका ने अपने नौसैनिक जहाजों और लड़ाकू विमानों की अतिरिक्त तैनाती की पुष्टि की, जबकि ईरान ने भी अपनी नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है।तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य विमानों ने उसकी समुद्री सीमा के निकट निगरानी उड़ानें भरीं। इसके जवाब में ईरानी सेना ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और कहा कि यदि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ तो वह "कड़ा और तत्काल जवाब" देगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसकी सैन्य गतिविधियां केवल अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं और उनका उद्देश्य क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर निर्यात होने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर सीधा असर डाल सकता है। तनाव बढ़ने की खबर के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली और निवेशकों की चिंता बढ़ गई।संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचने की अपील की है। यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों ने भी कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि यह तनाव और बढ़ा तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा।

संपादक की कलम से

मेलबर्न में आयोजित 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम केवल एक प्रवासी सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय के भारत के प्रति बढ़ते विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी था। हजारों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी ने यह स्पष्ट किया कि भारत की वैश्विक छवि लगातार मजबूत हुई है और भारतीय समुदाय आज विश्व मंच पर देश की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। ऐसे आयोजन भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊर्जा देते हैं और द्विपक्षीय संबंधों को जनस्तर पर भी मजबूती प्रदान करते हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विकसित भारत, अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियों और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का उल्लेख किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढांचे और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल मिशन, वैश्विक मंचों पर बढ़ता प्रभाव और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम भारत की बदलती क्षमता को दर्शाते हैं। यदि भारत वास्तव में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में सफल होता है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।साथ ही, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने की सहमति दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकती है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में विश्वसनीय साझेदारियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देशों के पास व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।हालांकि, किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में किए गए दावों और घोषणाओं की वास्तविक सफलता का आकलन उनके ठोस परिणामों से होगा। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब आर्थिक विकास के साथ रोजगार सृजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक समावेशन भी समान गति से आगे बढ़ें। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ घरेलू चुनौतियों का प्रभावी समाधान भी उतना ही आवश्यक है।भारत आज एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां उसकी वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हो रही है। इस अवसर को स्थायी उपलब्धि में बदलने के लिए दूरदर्शी नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन और राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता होगी। यदि विकास की यह गति निरंतर बनी रहती है और उसके लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचते हैं, तो विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की वास्तविकता बन सकता है।

सांसद के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी का अल्टीमेटम-

21 जुलाई से पहले फैसला कर लें नेता

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद कोयल मालिक के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और सांसदों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि जो लोग दबाव में हैं या पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे 21 जुलाई से पहले अपना फैसला कर लें।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की राज्यसभा सांसद कोयल मालिक के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर चल रही हलचल को खुलकर सामने ला दिया है। उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहली बार बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पार्टी के नेताओं और सांसदों को साफ संदेश दिया है कि जो भी नेता किसी तरह के दबाव में हैं या पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे 21 जुलाई के शहीद दिवस से पहले अपना फैसला कर लें। ममता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी किसी को रोककर नहीं रखना चाहती और जो जहां जाना चाहता है, वह बिना किसी हिचक के जा सकता है।ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कोयल मालिक का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी थी और इसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात भी की। ममता ने कहा कि वह उनके फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही दूसरे दलों के संपर्क में हैं या राजनीतिक दबाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे नेताओं को पार्टी के भीतर रहकर असमंजस की स्थिति पैदा करने के बजाय अपना रास्ता चुन लेना चाहिए।दरअसल, पिछले कुछ महीनों से टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के बाद टिकट वितरण, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर कई नेताओं में नाराजगी थी। हालांकि अब तक पार्टी नेतृत्व इन मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से बचता रहा, लेकिन कोयल मालिक के इस्तीफे के बाद ममता ने खुलकर अपनी बात रखी।इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा भी पार्टी छोड़कर बागी गुट में शामिल हो गए थे। हालांकि जाते-जाते उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी आज भी एक मजबूत जननेता हैं और उनके पास इतना जनाधार है कि वह पार्टी को दोबारा मजबूती से खड़ा कर सकती हैं। इसके बावजूद लगातार हो रहे इस्तीफों ने विपक्ष को टीएमसी पर हमला करने का मौका दे दिया है।गौरतलब है कि 21 जुलाई टीएमसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन पार्टी हर साल 'शहीद दिवस' के रूप में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इस बार ममता बनर्जी ने इसी तारीख को पार्टी नेताओं के लिए अंतिम समय-सीमा के रूप में तय कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल नाराज नेताओं के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन कायम रखने और विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को एकजुट करने की रणनीति भी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि 21 जुलाई से पहले टीएमसी में और कितने बड़े राजनीतिक फैसले सामने आते हैं।

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने हिंदू संस्कृति पर हमला बताते हुए कार्रवाई की मांग की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्रों को कथित तौर पर कलमा और सूरह फातिहा याद करने का होमवर्क दिए जाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने गुरुवार को स्कूल मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोलते हुए इसे 'हिंदू संस्कृति पर जबरन हमला' बताया। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि इस मामले को नजरअंदाज किया गया तो तेलंगाना के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। बंडी संजय ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ऑटो चालक भरत का मामला उठाते हुए कहा कि पुलिस और AIMIM के नेताओं ने कथित तौर पर उसके ऑटो पर लिखे एक संदेश को लेकर उसे परेशान किया। बंदी संजय ने सवाल उठाया, उन्होंने इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों और मजलिस नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो हिंदू परंपराओं और संस्कृति की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'इस बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनना तय है। हम हिंदू छात्रों के लिए तिलक लगाना अनिवार्य करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि हिंदू संस्कृति और परंपराओं का पालन हो।' बता दें कि हैदराबाद के सईदाबाद के इस स्कूल में कथित धार्मिक गृहकार्य को लेकर अभिभावकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने विवादित मामले से जुड़ी शिक्षिका को नौकरी से निकाल दिया और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पिछले साल मध्य प्रदेश से भी एक मामला सामने आया था जिसमें कलमा याद करके न आने पर एक शख्स ने एक युवती की पिटाई कर दी थी।

केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में धरना स्थल जंतर-मंतर पहुंचे। वहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आंदोलनकारी युवाओं और सोनम वांगचुक की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की आवाज को नजरअंदाज किया, तो आने वाले समय में उसे 2014 जैसी राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर उनकी जगह सोनम वांगचुक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक गुरुवार को अपने अनिश्चितकालीन अनशन के 19वें दिन में प्रवेश कर गए हैं । उनका यह आंदोलन साल 2026 की नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है। इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन मूल्यवान है और सरकार का दायित्व है कि उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। अदालत ने निर्देश दिया कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की प्रतिदिन डॉक्टरों द्वारा निगरानी की जाए। साथ ही सरकारी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार यदि किसी चिकित्सा जरूरत की आवश्यकता हो तो उसे बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम पहले से ही रोजाना सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर एक अतिरिक्त मेडिकल टीम भी तैनात की जा सकती है। यह आदेश वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) के निपटारे के दौरान दिया गया।

नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द

एमबीबीएस की 10 हजार तक सीटें बढ़ने की तैयारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी करने वाली है। करीब 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आसान और तेज की जाएगी। इसके अलावा एमबीबीएस सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट NEET (UG) 2026 का रिजल्ट 20 जुलाई 2026 तक जारी किया जा सकता है। इसके बाद देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट रिजल्ट स्कोर के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करती है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नेशनल मेडिकल कमिशन और काउंसलिंग कमिटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस को सरल बनाने पर चर्चा हुई। यह तय किया गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को कम समय में पूरा किया जाएगा। इस बार नीट री-एग्जाम होने के कारण एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने में पहले ही देरी हो गई है, ऐसे में काउंसलिंग का शेड्यूल इस तरह से तैयार किया

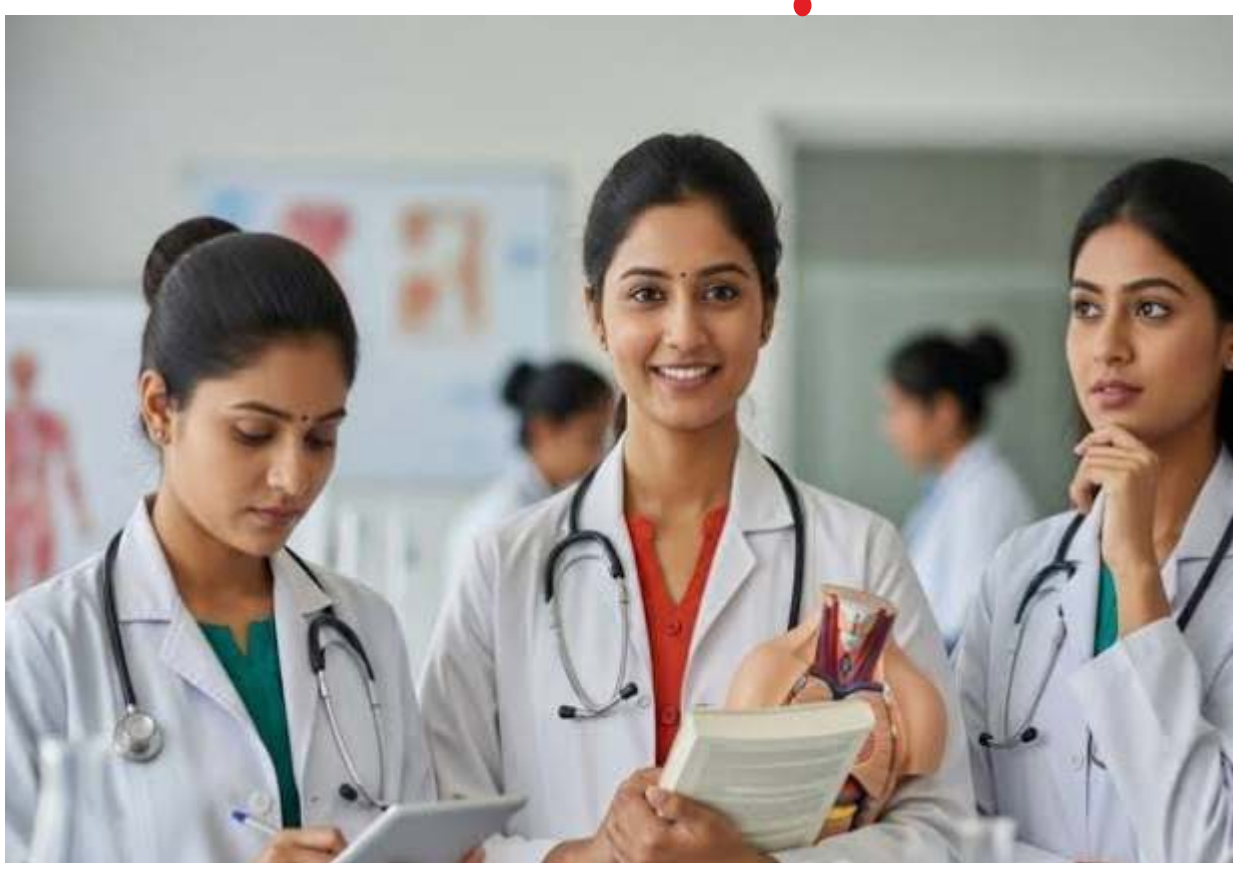

जा रहा है कि नया सेशन शुरू होने में ज्यादा देरी न हो। रिजल्ट के आते ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। नीट यूजी के टेस्ट में 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि 2026-27 के लिए MBBS की कितनी सीटें होंगी, इसकी डिटेल करीब करीब तय हो गई है और अगले कुछ दिनों में एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स (Seat Matrix) जारी कर दिया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि नए सेशन में एमबीबीएस की सीटों में 8 से 10 हजार का इजाफा होगा। पिछले वर्ष एमबीबीएस की 1.29 लाख सीटें थी, जो इस बार बढ़कर 1.40 लाख तक हो सकती हैं। मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि NEET-UG एक कानूनी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, जिसे NMC एक्ट- 2019 की धारा 14 के तहत इस एक्ट और अन्य लागू कानूनों के दायरे में आने वाले सभी मेडिकल संस्थानों में अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए शुरू किया गया था। जहां NMC, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट से जुड़े कानूनी, रेगुलेटरी और पॉलिसी से जुड़े ढांचे को बनाने के लिए ज़िम्मेदार कानूनी अथॉरिटी है, वहीं NTA परीक्षा आयोजित करने वाली तय एजेंसी के तौर पर काम करती है, जिसे परीक्षा के ऑपरेशनल संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। NMC को योग्यता शर्तें, सिलेबस, कॉमन काउंसलिंग प्रक्रिया और एडमिशन क्राइटेरिया तय करने का अधिकार देता है।

अब आपको dMAT एग्जाम देना होगा, जो APS डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का हिस्सा है

वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटीज, किफायती ट्यूशन फीस और बढ़िया करियर अवसर मुहैया कराने की वजह से जर्मनी भारतीय छात्रों के बीच एक पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल हजारों भारतीय यहां मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से एडमिशन को लेकर कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए अब एक नया एग्जाम लाया गया है, जो मास्टर्स एडमिशन के लिए जरूरी होगा। जर्मनी की एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर (APS) वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत एक नया 'डिजिटल मास्टर असेसमेंट टेस्ट' (dMAT) अनिवार्य किया जा रहा है। APS इंडिया और g.a.s.t. ने मिलकर इस एग्जाम को पेश किया है। अगर आप 2027 में जर्मनी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब आपको dMAT एग्जाम देना होगा, जो APS डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी किस तरह करनी होगी और ये एग्जाम किसके लिए है। dMAT एग्जाम जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हर स्टूडेंट के लिए है। अभी ये कुछ खास कैटेगरी और कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पर ही लागू होता है। अगर आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से जुड़ा मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस एग्जाम को देना होगा। अब यहां सवाल उठता है कि भारतीय स्टूडेंट्स dMAT की तैयारी कैसे करें और इसके लिए रिसोर्स कहां मिलेंगे? YES Germany के फाउंडर और स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट डॉ. गगन स्याल से यही सवाल किया गया। नवभारतटाइम्स डॉट कॉम के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'APS इंडिया और g.a.s.t. द्वारा शुरू किया गया डिजिटल मास्टर टेस्ट (dMAT) उन भारतीय छात्रों के लिए नई प्रक्रिया है, जो जर्मनी में मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। यह परीक्षा अभी कुछ चुनिंदा छात्रों के लिए शुरू की गई है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।'

पीवी सिंधु की जापान ओपन में प्रभावशाली जीत, क्वार्टर फ़ाइनल में प्रवेश

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रिटायर्ड हर्ट पर चुप्पी तोड़ी

इंग्लैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार उस पल पर चुप्पी तोड़ी है, जब उन्हें पारी के बीच मैदान छोड़ना पड़ा था। गिल ने बताया कि बल्लेबाजी के दौरान उन्हें तेज ऐंठन महसूस हुई, जिसकी वजह से वह रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह कोई गंभीर चोट नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि दूसरे एकदिवसीय मुकाबले तक वह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरेंगे। बता दें कि बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले एकदिवसीय मुकाबले में भारत को 259 रन का लक्ष्य मिला था। शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा 11 रन तथा विराट कोहली केवल 5 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। उस समय भारत का स्कोर 8.3 ओवर में 48 रन पर दो विकेट था और इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। ऐसे मुश्किल समय में शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 101 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को जीत की ओर बढ़ाया। मौजूद जानकारी के अनुसार, गिल ने 75 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। उन्होंने लगभग दो घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए परिस्थितियों के अनुसार अपना खेल बदला और जल्दबाजी से बचते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि ऐंठन बढ़ने के बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। उनके बाहर जाने के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल भी जल्दी आउट हो गए, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी। लेकिन वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को छह विकेट से जीत दिला दी। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वह दूसरे एकदिवसीय मुकाबले के लिए खुद को फिट महसूस कर रहे हैं। टीम के अभ्यास सत्र के दौरान भी उनकी गतिविधियां सामान्य नजर आईं।

गुरनूर बराड़ की आक्रामक फील्डिंग को स्तर-एक के उल्लंघन की श्रेणी में रखा

इंग्लैंड दौरे पर भारत को पहली जीत दिलाने वाले मुकाबले के बाद एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को चर्चा में ला दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर गुरनूर बराड़ को आधिकारिक चेतावनी जारी की है। साथ ही उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट्स भी जोड़ दिया गया है। मौजूद जानकारी के अनुसार यह घटना इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर के दौरान हुई थी। क्षेत्ररक्षण करते समय गुरनूर बराड़ ने गेंद उठाकर बल्लेबाज की दिशा में ऐसे अंदाज में फेंकी, जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अनुचित और संभावित रूप से खतरनाक माना। इसी आधार पर उन पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के स्तर-एक के नियम के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि गुरनूर बराड़ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी द्वारा प्रस्तावित सजा को भी मान लिया। इसके बाद इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह पिछले 24 महीनों में उनका पहला अनुशासन संबंधी मामला है, इसलिए उनके खाते में केवल एक डिमेरिट पॉइंट दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मैदान पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल भावना बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ऐसे मामलों को गंभीरता से देखती है। स्तर-एक के उल्लंघन में आधिकारिक चेतावनी, मैच फीस का कुछ हिस्सा काटने या एक से दो डिमेरिट पॉइंट्स देने का प्रावधान होता है। इस मामले में गुरनूर बराड़ को केवल चेतावनी और एक डिमेरिट पॉइंट की सजा मिली है।

रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी को रणनीतिक सुझाव दिया

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए विश्व कप प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बदलाव प्रतियोगिता को और बेहतर बनाएगा, लेकिन अगर क्रिकेट को सचमुच वैश्विक खेल बनाना है तो उभरती टीमों को नियमित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी मिलने चाहिए। अश्विन का मानना है कि केवल विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाने से खेल का विस्तार नहीं होगा, बल्कि छोटी टीमों को बड़े देशों के खिलाफ लगातार खेलने के अवसर मिलने चाहिए। बता दें कि आईसीसी ने हाल ही में 2027 के एकदिवसीय विश्व कप और 2028 के टी-20 विश्व कप के प्रारूप में बदलाव की घोषणा की है। नए प्रारूप के तहत एकदिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और प्रतियोगिता को तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। वहीं टी-20 विश्व कप में पहले के मुकाबले दूसरे चरण में अधिक टीमों को शामिल किया जाएगा, जिससे मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। मौजूद जानकारी के अनुसार, रविचंद्रन अश्विन ने सामाजिक माध्यम पर लिखा कि आईसीसी का यह फैसला प्रतिस्पर्धा के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि यदि अंतिम लक्ष्य क्रिकेट का विस्तार करना है तो उभरते देशों के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नेपाल, अमेरिका और आयरलैंड जैसी टीमों को हर द्विपक्षीय श्रृंखला में तीसरी टीम के रूप में शामिल किया जा सकता है। इससे इन देशों को केवल क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, स्कॉटलैंड और अमेरिका जैसी टीमों ने सीमित अवसर मिलने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। टी-20 विश्व कप में भी इन टीमों ने कई मजबूत देशों को कड़ी चुनौती देकर अपनी क्षमता साबित की थी।

महिला ने बताया कैसे 100 के बाद भी रहती हैं एक्टिव

101 साल की पत्रकार आज भी करती हैं जॉब

लंबी जिंदगी का राज क्या है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती उम्र के साथ सेहत, तेज दिमाग और जिंदगी जीने का उत्साह कैसे बरकरार रखा जाए. यानी जब तक जीवन है, तब तक उसे पूरे जोश और सक्रियता के साथ कैसे जिया जाए? वैज्ञानिक सालों से इसका जवाब तलाश रहे हैं. लेकिन अगर 100 साल की उम्र पार कर चुकी कोई महिला आज भी नौकरी कर रही हो, खुद अपना काम संभाल रही हो और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हो, तो उसकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए.इन दिनों सोशल मीडिया पर 101 वर्षीय पत्रकार एलीन लवीन की कहानी चर्चा में है. 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह काम कर रही हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन जी रही हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय हैं. हाल ही में टुडे डॉट

कॉम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लंबी, स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी के पीछे की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया, जिन्हें वह अपनी ऊर्जा और जिंदादिली की सबसे बड़ी वजह मानती हैं. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के वे तीन पहलू, जो लंबी उम्र का राज हो सकते हैं.

1. दिमाग को हमेशा सक्रिय रखें

एलीन कहती हैं कि वह खुद को एथलीट नहीं मानतीं. उनके मुताबिक, शरीर से ज्यादा जरूरी है कि दिमाग लगातार सक्रिय रहे. उनकी सुबह नाश्ते से शुरू होती है. इसके बाद वह नियमित रूप से द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ती हैं. साथ ही द न्यू यॉर्कर, प्रोपब्लिका, कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू और द हिल जैसे प्रकाशनों की खबरों पर भी नजर रखती हैं. क्रॉसवर्ड हल करना, ऑनलाइन लेक्चर सुनना और नई-नई चीजें सीखना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

2. काम करना कभी बंद मत कीजिए

एलीन का मानना है कि इंसान को तब तक सक्रिय रहना चाहिए, जब तक वह समाज में कुछ सार्थक योगदान दे सकता है. उन्होंने बताया कि उनकी मां हमेशा उन्हें सकारात्मक सोच रखने.

जानिए क्या है असली वजह

जापान में 'भूतिया' घर खरीदने लाइन क्यों लगा रहे लोग!

जापान की रियल एस्टेट मार्केट में इन दिनों एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जिन घरों को कभी लोग अपशगुन या डर मानकर खरीदने से कतराते थे, आज वही घर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं.

इन्हें जापान में जिको बुकेन (Jiko Bukken) कहा जाता है यानी वे प्रॉपर्टीज जहां कभी आत्महत्या, हत्या या किसी अकेले व्यक्ति की मौत हुई हो. दशकों से जापानी समाज में इन घरों को आध्यात्मिक रूप से सही नहीं माना जाता था लेकिन अब इनकी डिमांड जोरों पर है. आज के समय में जापान में रहने की लागत इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए अच्छे घरों तक पहुंचना

मुश्किल हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोक्यो जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं. ऐसे में जिको बुकेन घरों के भारी डिस्काउंट जो अक्सर बाजार भाव से 20 से 50 प्रतिशत तक कम होते हैं और बजट-फ्रेंडली खरीदारों और इन्वेस्टर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, अब लोग अंधविश्वास से ज्यादा अपनी जेब को अहमियत दे रहे हैं.

गुलाबी टोकरी से मिल सकता है प्यार?

डेटिंग ऐप्स के दौर में फिनलैंड के एक सुपरमार्केट का अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यहां शॉपिंग के दौरान गुलाबी टोकरी उठाना इस बात का संकेत माना जाता है कि ग्राहक सिंगल है और नए लोगों से बातचीत के लिए तैयार है.

डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के दौर में प्यार ढूंढ़ने के कई तरीके हैं, लेकिन फिनलैंड के एक सुपरमार्केट का अनोखा आइडिया इन दिनों दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां कस्टमर अगर गुलाबी रंग की शॉपिंग बास्केट उठाता है, तो इसका मतलब होता है कि वह सिंगल है और नए लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार है. अमेरिकी कंटेंट

क्रिएटर रोया फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस अनोखे कॉन्सेप्ट का वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह बताती हैं कि बास्केट पर 'सिंक्कु कोरी' लिखा है, जिसका फिनिश भाषा में मतलब 'सिंगल बास्केट' होता है. रोया वीडियो में कहती हैं कि अगर आपको किराने की दुकान में प्यार ढूंढ़ना है, तो बस गुलाबी टोकरी लेकर शॉपिंग कीजिए. शायद यहीं आपको अपना जीवनसाथी मिल जाए. फिनलैंड के कुछ सुपरमार्केट्स ने यह पहल सिंगल लोगों को सहज और सुरक्षित माहौल में एक-दूसरे से मिलने का मौका देने के लिए शुरू की थी. इसका मकसद डेटिंग ऐप्स या बार-कल्चर से अलग एक सामान्य सार्वजनिक जगह पर बातचीत की शुरुआत कराना है. हालांकि, यह सुविधा हर सुपरमार्केट में उपलब्ध नहीं है और केवल कुछ चुनिंदा स्टोर्स में ही देखने को मिलती है. क्या सच में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? 'सिंक्कु कोरी' यानी सिंगल बास्केट कोई आधिकारिक डेटिंग सर्विस नहीं है, बल्कि एक हल्के-फुल्के सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू किया गया.

लोगों को भा रहा तरीका

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि सबसे बड़ा डर यह होगा कि गुलाबी टोकरी लेकर पूरी शॉपिंग कर ली और कोई बात ही न करे. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसी टोकरी भी चाहिए, जो साफ बता दे कि वे शॉपिंग के दौरान किसी से बातचीत नहीं करना चाहते.

PoK में बगावत के कौन हैं तीन चेहरे

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की कमान किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, लेकिन जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर, सरदार अमन खान और सरदार उमर नजीर खान इस विरोध प्रदर्शन के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हैं. बिजली, महंगाई, टैक्स और स्थानीय अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन में इन नेताओं की भूमिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.

'द ओडिसी' की कहानी भारतीय दर्शकों को क्यों लगती है इतनी अपनी?

सिनेमा की दुनिया में जब भी हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) का नाम आता है, तो दर्शकों के दिमाग में टाइम ट्रेवल, स्पेस और उलझी हुई दिमागी कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन इस बार नोलन अपनी अगली बड़ी फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) के जरिए एक ऐसी कहानी बड़े पर्दे पर लाए हैं, जो लगभग 3,000 साल पुरानी है। होमर का यह प्राचीन ग्रीक महाकाव्य भले ही एक बिल्कुल अलग सभ्यता से आता हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रामायण और महाभारत जैसी महान गाथाएं पढ़कर बड़े हुए भारतीय दर्शकों को यह कहानी बिल्कुल अपनी और जानी-पहचानी सी लग सकती है। घर से बिछड़ा हुआ एक महानायक, सालों-साल का लंबा और कड़ा देश निकाला (वनवास), राक्षसों और जादुई ताकतों से भरा एक बेहद खतरनाक सफर, इंसानों की जिंदगी में दखल देते भगवान और घर पर अपने नायक का बेसब्री से इंतजार करता एक परिवार... कुछ जाना-पहचाना सा लगा न? यही वो भावनाएं और परिस्थितियां हैं, जो 'द ओडिसी', 'रामायण' और 'महाभारत' को एक ही धागे में पिरोती हैं। हालांकि, इन तीनों महाकाव्यों में कोई सीधा ऐतिहासिक संबंध नहीं है और न ही इस बात का कोई सबूत है कि होमर ने भारतीय ग्रंथों से कुछ लिया था। रामायण और महाभारत जहां भारत की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़े पवित्र ग्रंथ हैं, वहीं 'द ओडिसी' ग्रीक पौराणिक कथाओं पर आधारित एक महान साहित्यिक कृति है। फिर भी, जब हम इन्हें साथ रखते हैं, तो इनकी समानताओं को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। इन कहानियों का सबसे भावुक पहलू है— पीछे छूटे लोगों का इंतजार। ओडीसियस की पत्नी पेनेलोप 20 साल तक उसका इंतजार करती है, सीता का पूरा जीवन राम से जुदाई और संघर्ष में बीतता है, और द्रौपदी व कुंती पांडवों के वनवास का दर्द झेलती हैं। इसके अलावा, राजा की गैर-मौजूदगी में साम्राज्य पर जो संकट आता है, वह भी तीनों कहानियों में एक जैसा ही है।भले ही ओडीसियस अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हों, राम अपने 'धर्म' के लिए और पांडव नैतिक उलझनों के लिए- लेकिन इन सब का मूल संदेश एक ही है।

कुकरैल नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी लखनऊ चिड़ियाघर परिसर में बनेगा नया जू

कुकरैल नाइट सफारी के निदेशक रामकुमार ने बताया कि पहले चरण में नाइट सफारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में इसी परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया चिड़ियाघर भी विकसित किया जाएगा।

वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित कुकरैल नाइट सफारी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (लखनऊ चिड़ियाघर) के मौजूदा वन्यजीवों को कुकरैल नाइट सफारी में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय चिड़ियाघर परिसर में ही एक नया आधुनिक जू विकसित किया जाएगा। इससे लखनऊ में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब परियोजना को गति दी जाएगी। निर्माण कार्य केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा तय किए गए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।कुकरैल नाइट सफारी के निदेशक रामकुमार ने बताया कि पहले चरण में नाइट सफारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में इसी परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया चिड़ियाघर भी विकसित किया जाएगा। इस योजना के पूरा होने के बाद पर्यटकों को दिन और रात दोनों समय वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में देखने का अनूठा अनुभव मिलेगा। यह परियोजना लखनऊ को देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।प्रस्तावित नाइट सफारी में 54 से अधिक प्रजातियों के वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा। इसके लिए 38 से अधिक विशेष एन्क्लोजर बनाए जाएंगे। यहां एशियाटिक शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, दरियाई घोड़ा, ज़ेबरा, उड़न गिलहरी, घड़ियाल और मगरमच्छ सहित कई दुर्लभ वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि जानवरों को पारंपरिक लोहे के पिंजरों में रखने के बजाय बाधारहित खुले प्राकृतिक क्षेत्र (कैटल ग्रिड प्रणाली) में रखा जाएगा, जिससे उन्हें उनके प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण मिल सके।रामकुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है। आदेश का अध्ययन करने के बाद उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी और निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 206 करोड़ रुपये का बजट पहले ही मंजूर कर चुकी है तथा निर्माण एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है। वन विभाग को उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर 2026 तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद लखनऊ को देश की सबसे आधुनिक नाइट सफारी और वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रातभर बरसे बादल, लखनऊ में आज भी भारी बारिश की चेतावनी

लखनऊ में रातभर झमाझम बारिश हुई। आज तड़के 5:08 बजे से फिर से बरसात शुरू हो गई। लगातार जारी रिमझिम बारिश के बीच बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान बादलों की गरज-चमक भी बरकरार रहेगी। गुरुवार को 24 घंटे के अंदर 27.2 मिमी बारिश हुई, जो इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बरसात है। इससे पहले बुधवार को 18.4 डिग्री बारिश रिकॉर्ड की गईगुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अधिकतम आर्द्रता 94 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 74 फीसदी रही।

100 वर्ष पूरे होने पर प्रतिभा जोशी का सम्मान मुख्यमंत्री का संदेश लेकर घर पहुंचे अधिकारी

एक सदी का जीवन... उपलब्धियों, अनुशासन और समाज-सेवा से भरे सफर को बृहस्पतिवार को सरकार ने विशेष सम्मान दिया। इंदिरा नगर निवासी शतायु प्रतिभा जोशी के 100वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुभकामना एवं बधाई संदेश उनके घर पहुंचाया गया। डीएम विशाख जी, महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का संदेश सौंपा। इस अवसर पर उन्हें अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और "एक जनपद-एक उत्पाद" (ओडीओपी) का स्मृति उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की।

डीएम विशाख जी ने बताया कि वर्ष 1926 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मीं प्रतिभा जोशी का जीवन शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की प्रेरक मिसाल है। वर्ष 1940 में उन्होंने एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की परीक्षा में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 1946 में इंजीनियर तारा चरण जोशी से विवाह के बाद प्रतिभा जोशी ने परिवार और समाज, दोनों के प्रति अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए मफलर और बैज तैयार कर राष्ट्रसेवा में भी योगदान दिया। आज उनका परिवार तीन बेटों, दो बेटियों और कई पीढ़ियों तक विस्तृत हो चुका है। प्रतिभा जोशी ने अपनी लंबी आयु का श्रेय संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच को दिया। उन्होंने युवाओं से माता-पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों ने 100वें जन्मदिन का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी) महेंद्र पाल सिंह, एसडीएम सदर मनोज सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज

भगवान श्रीकृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन कर मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने झारखंड में कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को पक्का मुसलमान पांच वक्त का नमाजी बताया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मौलाना ने सनातन धर्म का अपमान कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मौलाना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। झारखंड में आयोजित एक धार्मिक सभा में मौलाना जर्जिस अंसारी का एक वीडियो वायरल होने के बाद भगवान श्रीकृष्ण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में मौलाना ने श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के दसवें श्लोक का हवाला देते हुए दावा किया है कि भगवान श्रीकृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे। इटावा के बाह अड्डा निवासी मौलाना जर्जिस अंसारी का भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम को लेकर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो झारखंड में 23 जून को आयोजित एक धार्मिक सभा का है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या कर दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि उसमें वर्णित ध्यान और साधना का आशय नमाज से है। वीडियो में वह भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि वह पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे। भगवान श्रीराम के बारे में भी इसी प्रकार का दावा किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद कई संतों, धार्मिक संगठनों और हिंदू संगठनों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है।

गलत इंजेक्शन लगाने से 9 माह की बच्ची की मौत

लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में 9 माह की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने और फर्जी बिल बनाकर शव नहीं देने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद बिना बिल का भुगतान कराए अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया। मामला गोमती नगर स्थित वात्सल्य अस्पताल का है। आज, 9 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे बारांबकी के मसौली निवासी लाल बाबू की बच्ची अस्पताल में भर्ती हुई थी। सुबह करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई। बाराबंकी के मसौली थाना निवासी लाल बाबू की 9 महीने की बेटी आस्था की 8 जुलाई की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में परिजन बच्ची को लेकर लखनऊ पहुंचे। 9 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे गोमतीनगर के वात्सल्य अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची के चाचा प्रवीण गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब पांच बजे आस्था को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसे ICU में भर्ती कर इलाज शुरू किया।

विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी

विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस महिलाओं को तवज्जो देगी। सियासी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश राजेंद्र पाल गौतम एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दिए है। इसके तहत बुधवार और बृहस्पितवार को प्रदेश मुख्यलाय में ताबड़तोड़ बैंठकें हुईं। विधानसभा क्षेत्रवार अब तक की गई तैयारी का जायजा लिया या। पूर्व उम्मीदवारों और विभिन्न विभागों एवं फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। संगठनात्मक तैयारी की समीक्षा की गई। देर शाम वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव के बाद अब तक क्षेत्र में चली गतिविधियों के बारे में जानकरी ली गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। करीब 35 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए

बृहस्पतिवार को महिला उम्मीदवारों से उनके चुनाव से जुड़े अनुभव जाने गए। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि जल्द ही उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह स्क्रीनिंग कई आधारों पर की जाएगी, जिनमें उनकी विश्वसनीयता, सामाजिक पकड़ और ज़मीनी स्तर पर किया गया काम शामिल है। सपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में हमने सम्मान और बराबरी की मांग की है, जिस पर शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा होगी। अभी ध्यान इस बात पर भी है कि सरकार के इशारे पर समाज में फैलाई गई गलतफहमियों को दूर किया जाए और पार्टी के विज़न को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी सर्व समाज को एकजुट करने में जुटी है। जल्द ही विधानसभा क्षेत्र और बूथवार कमेटियों की समीक्षा की जाएगी। हर बूथ कमेटी की प्रदेश मुख्यालय से भी निगरानी की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: उन्नाव में स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्त निगरानी

उन्नाव में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को भी निजी स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। यात्रीकर अधिकारी विनय पाण्डेय और संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के विभिन्न मार्गों पर स्कूल वैन और अन्य छात्र परिवहन वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस और नियमों के विपरीत संचालित वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग के अनुसार, 9 जुलाई तक इस अभियान के तहत कुल 35 स्कूल वाहनों को निरुद्ध किया जा चुका है, जबकि विभिन्न अनियमितताओं के चलते 55 वाहनों का चालान किया गया है। गुरुवार सुबह से दोपहर तक भी कई स्थानों पर जांच जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कई निजी स्कूल वैन बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और आवश्यक सुरक्षा मानकों के संचालित होती मिलीं। ऐसे वाहनों को तत्काल रोककर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। यात्रीकर अधिकारी विनय पाण्डेय और संजीव कुमार सिंह ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अपने वाहनों को स्कूल वाहन संबंधी निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार कराएं। इसमें वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने अभिभावकों से भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने का आग्रह किया है। यदि कोई वाहन बिना आवश्यक मानकों के बच्चों का परिवहन करता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल परिवहन विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे लगातार चलाया जाएगा। जिले में समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम करना है।

शुक्लागंज में गंगा नदी का जलस्तर बीते 24 घंटों में 21 सेंटीमीटर बढ़कर 110.390 मीटर हो गया

गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटों में गंगा नदी का जलस्तर 21 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। जिससे गंगा किनारे बसी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर संकट गहरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीते सोमवार को शाम छह बजे गंगा नदी का जलस्तर 110.180 मीटर रिकार्ड किया गया था। जो कि 24 घंटों के बाद मंगलवार को शाम छह बजे की पैमाइश में एक मीटर 21 सेंटीमीटर बढ़कर 110.390 मीटर पहुंच गया है। शुक्लागंज में चेतावनी बिंदु 112 मीटर पर व खतरे का निशान 113 मीटर पर है। बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से मनोहरनगर, बालूघाट, इंदिरानगर, शक्तिनगर, बहादुर बगिया, गंगानगर, रविदासनगर, आलमनगर, मिश्रा कालोनी, चंपापुरवा, गोताखोर आदि गंगा किनारे बस्तियों में रहने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ गई है।

स्वास्थ्य केंद्र कालूखेड़ा में लापरवाही उजागर निरीक्षण में कई कमियां सामने आईं

उन्नाव। पुरवा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) प्रमेश श्रीवास्तव ने गुरुवार दोपहर असोहा विकासखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) कालूखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां सामने आईं। अस्पताल की अधीक्षक डॉ. अलीफा अल्वी निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिलीं। निरीक्षण में पता चला कि अस्पताल में कुल चार अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें तीन स्थायी और एक अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं। एसडीएम ने ओपीडी पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें 9 जुलाई को 24 मरीजों के नाम दर्ज थे। हालांकि, पंजिका में मरीजों के मोबाइल नंबर अंकित नहीं पाए गए। इस पर एसडीएम ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के नाम, पते के साथ मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं। ड्यूटी रोस्टर के संबंध में पूछने पर कर्मचारियों ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन ड्यूटी करनी पड़ती है। रविवार के अवकाश के स्थान पर शुक्रवार को ड्यूटी समायोजित की जाती है। एसडीएम ने इस व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कई स्थानों पर फर्श टूटी हुई पाई गई, जिससे कीड़े निकलने और संक्रमण फैलने का खतरा बताया गया। अस्पताल में प्रकाश व्यवस्था भी बेहद खराब थी। कर्मचारियों ने बताया कि परिसर के पास विद्युत ट्रांसफार्मर न होने से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रहती है। अग्नि सुरक्षा के लिहाज से भी अस्पताल में बड़ी कमी सामने आई, जहां कोई भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं था। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेने पर कर्मचारियों ने विभागीय पोर्टल के माध्यम से बताया कि अस्पताल में 152 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जबकि 52 प्रकार की आवश्यक दवाएं स्टॉक में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। परिसर में कहीं भी आरओ सिस्टम स्थापित नहीं पाया गया।

NHAI का बड़ा फैसला! कानपुर-लखनऊ हाईवे का टोल बढ़ाने जा रहा

एक ओर लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे संचालन के बाद महंगे टोल के साथ जहां इस पर सफर करने वालों को बहुत कम समय में लखनऊ से कानपुर आना और जाना अब बेहद आसान हो गया है। वहीं कानपुर-लखनऊ हाईवे (एनएच-27) पर पहले दिन ही चार हजार वाहनों की संख्या कम दर्ज की गई। कमोवेश यही हाल बुधवार को भी रहा। बावजूद एनएचएआइ लखनऊ यूनिट नेशनल हाइवे कानपुर-लखनऊ हाईवे का टोल बढ़ाने जा रहा है। एनएचएआइ द्वारा टोल बढ़ाने पर अब तक पहली बार एक वित्तीय वर्ष में दोबारा टोल बढ़ने का रिकार्ड बनेगा। अभी तक एनएचएआइ हर साल 31 मार्च रात 12 बजे के बाद टोल में वार्षिक वृद्धि करता रहा है। जिसमें मार्च 31, 2026-27 में पांच से 45 रुपये तक वृद्धि के रूप में दर्ज की गई है। इसमें भी पिछले वर्ष की तरह कार का टोल इस बार भी नहीं बढ़ाया था। जबकि, कामर्शियल वाहनों से लेकर बड़े ट्रकों तक पांच से 45 रुपये की टोल वृद्धि की गई थी। अब एनएचएआइ पीडी नकुल वर्मा का कहना है कि हम कानपुर लखनऊ हाईवे पर टोल बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि कार से लेकर बड़े वाहनों तक भी यह वृद्धि अधिकतम 30 रुपये तक होगी। पीडी ने बताया कि एप्रूवल के लिए मंत्रालय पत्र गया हुआ है। जिसके बाद एक से डेढ़ माह के बीच एप्रूवल मिलते ही टोल वृद्धि लागू कर दी जाएगी।टोल वृद्धि के पीछे पीडी ने तर्क दिया है कि लखनऊ से बनी तक लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर फ्री है। वाहन सवार आराम से इस 18 किमी मार्ग का सफर मुफ्त में कर रहे हैं। लेकिन बनी पहुंचते ही सर्विस रोड से कानपुर लखनऊ हाईवे पर आ जाते हैं। उधर हाल ही में 102 करोड़ से हाईवे का ओवरले के साथ सभी सड़क सुरक्षा व्यवस्थाएं चौकस की गई हैं। जिससे वाहन सवार सुगमता का अहसास कर रहे हैं। पीडी ने बताया कि अप्रूवल के बाद बढ़ा हुआ शुल्क नवाबगंज टोल प्लाजा से वसूला जाने लगेगा।चालू वित्तीय वर्ष में मासिक पास की दरों में न्यूनतम 80 रुपये तो अधिकतम 520 रुपये की बढ़ोतरी वाहन के आकार के अनुसार की गई है। इसमें भी 15 से 30 रुपये टोल शुल्क की बढ़ोतरी होगी। जिसके बाद न्यूनतम 100 रुपये तक अधिकतम 550 रुपये का शुल्क पड़ेगा।

खनऊ-कानपुर हाईवे पर कानपुर जाने वाली लेन पर तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे डंपर से भिड़ गया

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर कानपुर जाने वाली लेन पर तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे डंपर से भिड़ गया। इससे क्षतिग्रस्त डंपर खड़ा होने से हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लग गई। दो घंटे बाद क्षतिग्रस्त डंपर हटाने पर यातायात सामान्य हो सका। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव के पास बुधवार को सुबह 10 बजे लखनऊ-कानपुर हाईवे पर लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे दूसरे डंपर में पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे वाला डंपर क्षतिग्रस्त होकर बीच सड़क पर ही खड़ा हो गया। घटना के बाद क्षतिग्रस्त डंपर का चालक भाग गया। आगे वाला डंपर भी चालक लेकर निकल गया। बीच सड़क पर डंपर खड़े होने से हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर देखते ही देखते करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उमस भरी गर्मी में राहगीर और यात्री जाम में फंसकर परेशान होते रहे। करीब दो घंटे बाद क्षतिग्रस्त डंपर को हटाया गया। इस दौरान हाईवे की एक लेन पर वाहन रेंगते रहे। एसओ अरविंद पांडेय ने बताया कि डंपर चालक मौके से भाग गया है। हाइड्रा की मदद से डंपर को हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया गया है।

माखी दुष्कर्म पीड़िता ने चाचा को इंसाफ दिलाने के लिए PM और न्यायपालिका को लिखा लेटर

माखी दुष्कर्म पीड़िता ने तिहाड़ जेल में बंद चाचा को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री, न्यायपालिका व देश के लोगों से अपील करते हुए एक पत्र लिखकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है। उसके चाचा वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर पिछले सात-आठ वर्षों से जेल में रखा गया है। आरोप है कि विचाराधीन बंदी होने के बावजूद उन्हें अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। वर्तमान में तिहाड़ जेल संख्या 8/9 में निरुद्ध चाचा पिछले दो दिनों से अपने संवैधानिक अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, जिससे परिवार परेशान है। दुष्कर्म पीड़िता ने पत्र में कहा कि यदि उसके परिवार के हिस्से में न्याय नहीं लिखा है तो उन्हें तिल-तिल मरने के लिए न छोड़ा जाए। उसने परिवार के साथ हुए सभी अत्याचारों की निष्पक्ष जांच हो। चाचा के साथ हुए अन्याय की जांच, तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने व पूरे परिवार को भयमुक्त वातावरण और संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि वह किसी विशेष कृपा की नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को मिले न्याय के अधिकार की मांग कर रही है। कहा कि दुष्कर्म की घटना ने केवल उसकी अस्मिता ही नहीं छीनी, बल्कि पूरे परिवार का जीवन तबाह कर दिया। उसने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई, जबकि मुकदमे की प्रमुख पैरवी कर रही उसकी चाची की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद से परिवार को लगातार आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ

35 करोड़ पौधों के लक्ष्य के साथ यूपी में महावृक्षारोपण अभियान शुरू

सरकार के अनुसार इस अभियान में वन विभाग के अलावा कृषि, शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास, सिंचाई, पंचायती राज और अन्य विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पौधारोपण के लिए पहले से स्थान चिन्हित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 जुलाई को राज्यव्यापी महावृक्षारोपण अभियान-2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस वर्ष सरकार ने एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे अब तक का देश का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान माना जा रहा है। अभियान की थीम "एक पेड़ मां के नाम" रखी गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाने का संदेश दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वृक्ष भविष्य की पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों को अभियान को जन आंदोलन बनाने का निर्देश दिया।सरकार के अनुसार इस अभियान में वन विभाग के अलावा कृषि, शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास, सिंचाई, पंचायती राज और अन्य विभागों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पौधारोपण के लिए पहले से स्थान चिन्हित किए गए हैं। सड़क किनारे, नदी तटों, स्कूल परिसरों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम समाज की भूमि और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं।वन विभाग ने बताया कि इस बार फलदार, औषधीय और छायादार पौधों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इनमें नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, सहजन, आंवला, जामुन और आम जैसे पौधे शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य केवल हरित क्षेत्र बढ़ाना ही नहीं, बल्कि जैव विविधता को मजबूत करना और भूजल संरक्षण में भी योगदान देना है। अभियान की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। प्रत्येक जिले को पौधारोपण की वास्तविक समय की रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन और जीआईएस तकनीक की मदद से पौधों की निगरानी भी की जाएगी, ताकि लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर सुनिश्चित की जा सके।पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लगाए गए पौधों का नियमित संरक्षण किया गया तो उत्तर प्रदेश का हरित क्षेत्र बढ़ाने, प्रदूषण कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाने और भूजल स्तर सुधारने में यह अभियान मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार ने आम नागरिकों से भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने और पौधों की जिम्मेदारी लेने की अपील की है।

यूपी में 16 जुलाई से शुरू हुई डीएलएड (DElEd) 2026 प्रवेश प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए 16 जुलाई का दिन महत्वपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) 2026 की प्रवेश प्रक्रिया के तहत राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेशभर में काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।मेरिट सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने आधिकारिक पोर्टल पर अपने अंक और रैंक की जांच शुरू कर दी। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। मेरिट सूची तैयार करते समय निर्धारित आरक्षण नियमों और पात्रता मानकों का पालन किया गया है। अब सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी पसंद के संस्थानों का चयन करना होगा।परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा और प्रवेश से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका दावा स्वतः निरस्त माना जा सकता है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। डीएलएड पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक तैयार करने वाला प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हर वर्ष हजारों विद्यार्थी इस कोर्स में प्रवेश लेते हैं और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर

यूपी पुलिस का AI ट्रैफिक सिस्टम सफल, प्रयागराज और गाजियाबाद में जाम में बड़ी कमी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रैफिक प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सफल प्रयोग करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरेट में लागू किए गए A I आधारित रेड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन (RTC) सिस्टम से प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज और गाजियाबाद में इस तकनीक का सबसे अधिक सकारात्मक असर देखने को मिला है, जबकि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में भी यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुचारू हुई है।यह AI सिस्टम गूगल के रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा, सीसीटीवी कैमरों और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नलों की मदद से काम करता है। सिस्टम लगातार सड़कों पर वाहनों की आवाजाही का विश्लेषण करता है और जहां जाम की संभावना होती है, वहां पहले से ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट भेज देता है। इसके आधार पर सिग्नलों का समय बदला जाता है, वैकल्पिक मार्ग खोले जाते हैं और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाता है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले ट्रैफिक जाम की जानकारी मिलने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब AI तकनीक के कारण कुछ ही मिनटों में स्थिति का विश्लेषण कर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इससे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी तेजी से रास्ता मिल रहा है। त्योहारों, वीआईपी मूवमेंट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इस तकनीक के अच्छे परिणाम सामने आए हैं।राज्य सरकार का लक्ष्य इस तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाना है। आने वाले समय में इसे सभी प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही A I आधारित ट्रैफिक एनालिटिक्स को ई-चालान प्रणाली और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, ताकि यातायात प्रबंधन पूरी तरह तकनीक आधारित हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था भविष्य के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रयागराज महाकुंभ 2027 की तैयारियां तेज, योगी सरकार ने परियोजनाओं की समीक्षा कर दिए समयबद्ध कार्य के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ-2027 की तैयारियों को तेज कर दिया है।16 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और महाकुंभ से जुड़े कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।सरकार के अनुसार महाकुंभ में इस बार देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सड़क, पुल, घाट, पेयजल, सीवरेज, बिजली, पार्किंग और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए अस्थायी और स्थायी ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि संगम क्षेत्र में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और प्रशासनिक क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन भी है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने विशेष रूप से रेलवे, स्वास्थ्य, नगर विकास, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।बैठक में डिजिटल सुविधाओं पर भी जोर दिया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सूचना प्रणाली, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीसीटीवी निगरानी और A I आधारित भीड़ प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाने की योजना पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य है कि महाकुंभ-2027 को तकनीक और व्यवस्थाओं के लिहाज से अब तक का सबसे सुव्यवस्थित आयोजन बनाया जाए।